आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
वर्ष 1, अंक 1, जून 2015, पृ. 1–7

भूमंडलीकरण : एक समाजशास्त्रीय विवेचन

वीरेन्द्र पाल सिंह*

भारतीय समाज एवं संस्कृति में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन हो रहे है। भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ 1990 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में हुआ। वास्तव में इसको अपनाने के पीछे उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब अवस्था थी। यह एक ऐसा काल था जब वैश्विक स्तर पर व्यापार तथा अन्र्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए व्यापार के क्षेत्र में कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित कर दी गयी थी जिन्हें डंकल प्रस्ताव (Duncal Proposal) के नाम से जाना जाता था। सभी राष्ट्रों पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाब डाला जा रहा था। जिसे गैट (GATT) के नाम से जाना जाता है। इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात कोई भी राष्ट्र नयी आर्थिक नीति–जिसके तीन प्रमुख संघटक–भूमंडलीकरण निजीकरण, तथा उदारवाद (Globalization, Privatization and liberalisation) थे, को अपनाने के लिए बाध्य था। भारत ने वर्ष 1993 में गैट संधि पर हस्ताक्षर किये तथा इसके साथ ही भारत में भूमंडलीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ। जिसके फलस्वरूप आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था को नयी वैश्विक अर्थव्यवस्था (New Global Economy) से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण का प्रयोग विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अर्थों में किया है। तथा इसके कई अर्थ है तथा इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। यह सरकार की नीति का एक भाग भी है, जिसका मानना है कि भूमंडलीकरण निजीकरण तथा उदारवाद की नीति के माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्थां की सभी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। साथ ही भूंमंडलीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी आन्दोलन भी खड़ा हो गया है। सामान्य जनों में भी यह एक चर्चा का विषय है कि क्या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया सही है या यह समाज के लिए हानिकारक है। भूमंडलीकरण से विभिन्न मुद्दे जुड़े है तथा इन सभी पर इस समय चर्चा करना सम्भव नहीं हैं। अतः इस पेपर में मेरा ध्यान प्रमुख रूप से इसके समाजशास्त्रीय पक्षो ंपर केन्द्रित रहेगा।

भूमंडलीकरण में सामाजिक सम्बन्धों तथा विनियमों के रूपान्तरण सम्वन्धी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका मूल्यांकन उनकी व्यापकता, तीव्रता, वेग तथा प्रभाव के रूप में किया जाता है तथा इनके द्वारा क्रियाओं, अन्तःक्रियाओं तथा शक्ति प्रयोग के परामहाद्वीपीय (Transcontinental) अथवा अन्र्तक्षेत्रीय प्रवाहों तथा नेटवर्कों को उत्पन्न किया जाता है।

भूमंडलीकरण की कुछ आवश्यक विशेषताएं निम्नलिखित है :

1. भूमंडलीकरण विश्व के सभी व्यक्तियों को आभासी (virtually) रूप से प्रभावित करता है।
2. इस समय विश्व में हो रहे प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को लाने वाली केन्द्रीय परिचालन शक्ति भूमंडलीकरण ही है।
3. भूमंडलीकरण टेक्नॉलाजी, आर्थिक गविविधि, शासन, संचार आदि क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों का परिणाम है। परिवर्तन की ये प्रक्रियाएं परस्पर गहनतापूर्वक अन्र्तसंबद्ध हैं।

***प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सेन्टर फॉर ग्लोबेलाइजेशन एण्ड डवलेपमेन्ट स्टडीज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद**

4. इन सभी क्षेत्रो में होने वाले विकास परावर्तनीय तथा एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं जिससे इनके मध्य कारण तथा परिणाम के सम्बन्ध को स्थापित करना कठिन है तथा इनका कोई पूर्व इतिहास भी नहीं है।
5. भूमंडलीकरण में व्यापार, निवेश, प्रवजन, सांस्कृतिक गतिविधियों, पर्यावरण के क्षेत्र में सीमा पार हो रहे प्रवाहों के समकालीन प्रतिमान भी हैं।
6. ये प्रवाह सभी देशों का आभासी रूप से एकीकरण करते हुए उन्हें एक वृहद् भूमंडलीकष्त व्यवस्था (larger global system) में लाते हैं जिससे सभी स्तरों पर बड़े सामाजिक रूपान्तरण (social transformation) घटित होते हैं।
7. भूमंडलीकरण एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है।
8. भूमंडलीकरण का अर्थ भूमंडलीकृत संस्तरण व्यवस्था के नये स्वरूपों के विकास से है जिसमें कुछ व्यक्ति, समुदाय, देश अथवा क्षेत्र, शक्ति तथा समबद्धता के (भूमंडलीकृत) नेटवर्क में एकीकृत हो जाते है जबकि दूसरे इससे बाहर निकल जाते है या किनारे हो जाते है। (excluded or marginalized)।
9. ये नये विभाजन 'पूर्व–पश्चिम', उत्तर–दक्षिण के पुराने संघभेदों को परस्पर काटते है। शीतयुद्ध के बाद के समय में सामाजिक पृथक्कीकरण (Social exclusion) विश्व के सभी भागों में पाया जाने लगा है यहां तक पुराने औद्योगिक देशों के औद्योगिक क्षेत्र भी जहाँ पहले बड़ी संख्या में उद्योग थे परन्तु आज उनका महत्व तथा सम्पदा घट गयी हैं।
10. यद्यपि भूमंडलीकरण के कारण पृथक्कीकरण सबसे विस्तश्त तथा गंभीर रूप में अभी भी दक्षिण को ही प्रभावित करता है : वस्तुतः पूरे अफ्रीका के साथ ही एशिया के विस्तश्त भूभाग तथा लेटिन अमेरिकी क्षेत्रों में असमर्थता (Disempowerment) तथा दरिद्रता (गरीबी) (impoverishment) का अनुभव व्यापक रुप से किया जा सकेगा।
11. भूमंडलीकरण को राष्ट्र की शक्ति में सामान्य कमी के समतुल्य नहीं माना जा सकता। बल्कि जैसे–जैसे भूमंडलीकरण की शक्तियॉ द्वारा क्षेत्र तथा सार्वभौमिकता के मध्य्य के गठजोड़ को नकारा जाता है, वैसे–वैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैष्विक स्तर पर शासन के नये स्वरूप उभरने लगते है। साथ ही प्रभु राज्यों की सैनिक तथा आर्थिक शक्ति अभी भी एक निर्णायक भूमिका का निर्वाह कर रही है।
12. भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को इसके आर्थिक पक्ष से प्रारम्भ करके भली प्रकार से समझा जा सकता है। जिसे आज हम भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था (Global Economy) के नाम से जानते है।
13. भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था (Global Economy) एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसकी केन्द्रीय गतिविधियां एक इकाई के रूप में वास्तविक समय में भूमंडलीय स्तर पर कार्य करती है। जिसके कारण पूंजी बाजार विश्वव्यापी स्तर पर अर्न्तसंबद्ध (inter connected) रहते है जिससे इन सभी दशों में बचत तथा निवेश अपने कार्य सम्पादन हेतु वैश्विक वित्तीय बाजारों (global financial markets) के उद्विकास तथा व्यवहार पर निर्भर करते हैं।
14. उत्पादन, सेवा, तथा वित्तीय (finance) क्षेत्र में बहु राष्ट्रीय कम्पनियॉ वैश्विक अर्थव्यवस्था के अन्तःभाग या कोर का निर्माण करती हैं।
15. विज्ञान एवं टेक्नॉलाजी के उच्चतम घेरे जो सकल टेक्नालॉजिकल विकास को नियन्त्रिण करते हैं व इसे एक निश्चित आकार देते है उनका केन्द्रीकरण विश्व के कुछ दर्जन रिसर्च सेन्टरों पर है। पूरे विश्व में नवाचारों के ये केन्द्र प्रमुख रूप से अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा जापान में है। रूस, भारत, तथा चीन के इंजीनियर (प्रायः बहुत उच्च कोटि की दक्षता वाले) जब वैज्ञानिक विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुँच जाते हैं, तो वे अपनी आगे की रिसर्च को तभी जारी रख सकते हैं जब तक कि वे वे स्वयं को इन केन्द्रों से सम्बद्ध (linking) न कर लें।

जहाँ एक ओर उच्च कौशल युक्त श्रमिकों का भी अधिक से अधिक भूमंडलीकरण हो रहा है। वहीं इसके साथ–साथ अधिकतर रोजगार तथा व्यक्तियों का भूमंडलीकरण नहीं हो रहा है। वास्तव में तो वे स्थानीय व क्षेत्रीय हैं परन्तु उनके व्यवसाय, उनके भाग्य, उनकी जीवन शैली आदि अन्ततः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकृत सेक्टर पर अथवा पूंजी उत्पादन एवं व्यापार के भूमंडलीकृत नेटवर्कों पर निर्भर करते हैं।

भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रुप से नयी है, क्योंकि मात्र पिछले दो दशकों में इसने भूमंडलीय स्तर पर एक इकाई के रुप में कार्य करने हेतु आवश्यक टेक्नॉलोजिकल आधारभूत ढांचा खडा कर लिया है, जैसे, टैलीकम्यूनीकेशन्स, सूचना तन्त्र, माइक्रो–इलेक्ट्रोनिक पर आधारित उत्पादन एवं प्रोसेसिंग, सूचना पर आधारित वायु यातायात, कन्टेनर कार्गो यातायात, उच्च वेगीय रेल सेवाएं, विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाएं आदि।
फिर भी यदि हम यह मान भी लें कि नयी भूमंडलीकष्त अर्थव्यवस्था ने पूरे विश्व को आच्छादित कर दिया है तथा यदि प्रत्येक स्थान तथा सभी क्षेत्र इसकी कार्यप्रणाली से प्रभावित हो भी जाते हैं तो भी प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक व्यक्ति इसमें सीधे सम्मिलित नहीं हो सकता। वास्तव में अधिकतर लोग तथा अधिकतर भूभाग या तो उत्पादनकर्ता के रुप में अथवा उपभोक्ता के रुप में अथवा दोनों रुपों में इससे या तो अलग हो जाते हैं अथवा इससे बाहर हो जाते हैं।

इस नयी भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था की प्रकृति लचीली है। इसका यह लचीलापन पूरी व्यवस्था को हर उस वस्तु से जोड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है जो कि (प्रभुशाली मूल्यों तथा हितों के अनुसार) 'मूल्यवान' हैं। साथ ही हर उस वस्तु को असम्बद्ध करने की प्रवृत्ति रखता है जो 'मूल्यविहीन' हो गयी है या जो मूल्यवान नहीं रह गयी है।

आज के इस सूचना युग में गठित इस नयी भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसकी वह सामर्थ्य है जिसके द्वारा यह व्यक्तियों, क्षेत्रों तथा गतिविधियों को एक साथ सम्मिलित अथवा पृथक कर देती है।

भूमंडलीकरण की इस प्रकार की चुनावपूर्ण एवं विखण्डीकृत प्रक्रियाएं हमारे समाज के अन्य पक्षों में भी घटित हो रही हैं। जिनमें मीडिया, साइंस, संस्कृति तथा सूचना के क्षेत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

जहाँ तक भूमंडलीकरण के राजनीतिक पक्ष का प्रश्न है इस क्षेत्र में इसके प्रभाव को लेकर एक नयी बहस छिड़ी हुई है। इस बहस का प्रमुख केन्द्र इस प्रश्न पर है कि क्या भूमंडलीकरण के फलस्वरूप 'राष्ट्र–राज्य' कमजोर हो जायेंगे या इनका स्थान एक भूमंडलीकृत राज्य–व्यवस्था ले लेगी। इन मुद्दों का परीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण **'राष्ट्र–राज्यों' को समाप्त नहीं करते** परन्तु ये मूलभूत रूप से न केवल इनकी भूमिका को पुनः परिभाषित करते है अपितु इनके संचालन (operation) को भी प्रभावित करते हैं।

केन्द्रीय बैंक (जैसे World Bank) वित्तीय बाजारों में भूमंडलीकृत प्रवाहों की प्रवृत्तियों को नही रोक सकते तथा ये वित्तीय बाजार हमेशा आर्थिक नियमों से संचालित नही होते अपितु विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे सूचना–विक्षोभों (Information turbulences) से निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए–मिस्र या लीबिया से आने वाली सूचनाएं मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।

राष्ट्रीय सरकारे पूँजी तथा सूचना के वैश्विक प्रवाहों को प्रबन्धन करने की कुछ क्षमता को बनाये रखने के लिए परस्पर झुकती है तथा या तो सुपरा–नेशनल (Supranational) संस्थाओं का निर्माण करती है अथवा उनके साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं। इन संस्थाओं में International Monetary Funal (IMF) तथा यूरोपियन यूनियन (EU) अथवा NAFTA अथवा दूसरी क्षेत्रीय ऐजन्सियों का शामिल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ये 'राष्ट्र–राज्य' अपनी सार्वभौमिकता को काफी मात्रा में खो बैठते हैं। इनका अस्तित्व तो बना रहता है परन्तु **'राज्य के एक नये स्वरूप में'**। जो इन सुपरनेशनल संस्थाओं, राश्ट्र–राज्यों, क्षेत्रीय तथा स्थानीय शासन निकायों यहां तक कि गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) को अन्तःक्रिया तथा साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया के एक नेटवर्क में जोड़ती है। जो सूचना यूग का एक प्रचलित स्वरूप बन जाता है। इसे 'नेटवर्क–स्टेट' या ''नेटवर्क राज्य' की संज्ञा दी जा सकती हैं।

इस सूचना युग का प्रमुख संगठनात्मक स्वरूप (critical organizational form) 'नेटवर्किंग' (Networking) है। जिसके अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण विभेद यह है कोई व्यक्ति, वस्तु,, क्षेत्र, अथवा गतिविधि इस नेटवर्क से जुड़ी है अथवा नहीं। यदि आप इस 'नेटवर्क' में है तो आप इस भूमंडलीकृत व्यवस्था से जुड़े हुए है तथा

आपके जीवन–अवसरों में बृद्धि हो जायेगी परन्तु यदि आप इस व्यवस्था से बाहर हैं तो आप 'Excluded' अथवा 'switched off' है। तथा आपके जीवन अवसर समाप्त होते जायेंगे क्योंकि इस व्यवस्था में हर वह वस्तु जो मूल्यवान है, एक अन्तःक्रियात्मक विश्वव्यापी वैब (world wide web) के इर्द गिर्द संगठित है।

अतः भूमंडलीकरण एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें जहां एक ओर कुछ व्यक्ति सम्मिलित होते जाते हैं। वही दूसरी और अनेकों व्यक्ति मूल्य विहीन होकर इस व्यवस्था से बाहर होते जाते हैं।

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न पहलूओं को प्रभावित किया है। एक समाजशास्त्रीय प्रघटना के रूप में इसका विवेचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, भूमंडलीकरण एक संरचनात्मक प्रक्रिया के रूप में; द्वितीय, भूमंडलीकरण एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में।

संरचनात्मक प्रक्रिया के रूप में भूमंडलीकरण समाज की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी है जैसे सामाजिक स्तरीकरण, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया संगठन, धार्मिक संगठन आदि।

सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में यह सामाजिक मूल्यों, नैतिकता, सामाजिक आदर्शो, सामाजिक विश्वासों, जनमत निर्माण आदि प्रक्रियाओं से सम्बन्ध है।

इसके अलावा इसका विश्लेषण दो स्तरों पर किया जा सकता है।

1. विश्व स्तर पर 2. स्थानीय स्तर पर।

वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक इकाईयों अथवा संगठनों का निर्माण कर रहा है। इनको हम कारपोरेट जगत के रूप में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में, IMF, WTO जैसी वैश्विक ऐजेन्सियों, मानवाधिकार संगठनों, विश्व मीडिया संगठनों, धार्मिक संगठनों के वैश्विक विस्तार आदि के रूप में देख सकते हैं। ये सभी विश्व स्तर के संगठन है तथा इनकी संस्तरणीकृत संरचना विश्व स्तर पर, महाद्वीपीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर होते हुए स्थानीय स्तर तक जाती है जिसमें विभिन्न व्यक्ति, समूह संगठन अन्तः क्रिया के भूमंडलीकृत नेटवर्क से सम्बद्ध होते है। ये सभी संगठन आन्तरिक रूप से आपस में तथा बाहय रूप में अन्य क्षेत्रों के संगठनों से प्रक्रार्यात्मक रूप से सम्बद्ध रहते हैं तथा निरन्तर क्रियाशील रहते हैं। ये संगठन जहां एक ओर वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे होते हैं वही इन्हें स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय सामाजिक संरचना तथा संस्कृति से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है।

भारतीय समाज में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के संरचनात्मक पहलूओं को समझने के लिए इसको सामाजिक संस्तरण व्यवस्था के सन्दर्भ में देखना होगा।

परम्परागत भारतीय सामाजिक संस्तरण व्यवस्था मूलरूप से जाति व्यवस्था पर आधारित थी। अतः भूमंडलीकरण का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे समझने की आवश्यकता है। जाति व्यवस्था की दो प्रकार की विशेषताएं है : 1. केन्द्रीय विशेषताएं 2. परिधिय विशष्शताएं। जन्म पर आधारित सदस्यता, अर्न्तविवाह तथा सोपान–क्रम (hierarchy) इसकी मूलभूत विशेषताएं है जबकि दूसरी विशेषताएं–खान–पान सम्बन्धी प्रतिबन्ध, व्यवसाय का चुनाव, तथा कुछ विशिष्ट जातियों के साथ सामाजिक अन्तःक्रिया सम्बन्धी प्रतिबन्धों को परिधीय विशेषताओं में रखा जाता है। (अटल 1968) पिछले कुछ दशकों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप जाति की परिधीय विशेषताओं का कठोरता से पालन नहीं किया जाता। वास्तव में अर्न्तविवाह जाति की वह मूलभूत विशेषता है जो इसके अस्तित्व को निरन्तरता प्रदान करती है। अन्य दो विशेषताएं–जन्म पर आधारित सदस्यता, तथा सोपान–क्रम की निरन्तरता का मूल आधार भी यही है। यदि भूमंडलीकरण सामाजिक रूपान्तरण की प्रक्रिया है तो क्या यह जाति संस्तरण व्यवस्था को भी रूपान्तरित कर पायेगी अथवा नहीं।

एक संरचनात्मक प्रक्रिया के रूप में भूमंडलीकरण विभिन्न स्तरों पर सामाजिक असमानता उत्पन्न कर रहा है। भूमण्डलीकरण के दौर में जहां कुछ आर्थिक वृद्धि की दर में वृद्धि हुई है वही कृषि के क्षेत्र में भारी गिरावट देखने को मिलती है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की मात्रा में वृद्धि होगी। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवजन में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेगी जबकि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों

में वृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर उद्योग धन्धों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भूमि अधिग्रहण अधिक–से–अधिक होगा। इसके कारण किसानों में भूमिविहीनता बढ़ेगी तथा भूमि उपयोग के प्रतिमानों में भी परिवर्तन होगा। वही सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे के चलते ये सभी धीरे–धीरे निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा खरीद लिये जायेंगे। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार कम होते जायेंगे तथा निजी क्षेत्र में रोजगार अधिक होते जायेंगे। इनका नियन्त्रण वैश्विक, महाद्वीपीय, राश्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तरों पर परस्पर सम्बद्ध निजी कम्पनियों का नियन्त्रण बढ़ता जायेगा। सरकार की स्थिति दिन–प्रतिदिन कमजोर होती जायेगी। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप भारी मात्रा में प्रवजन होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। यह प्रवजन विभिन्न स्तरों पर तथा भौगोलिक रूप से विश्व व्यापी होगा। लोग रोजगार की तलाश में दूसरे दशों में जाने को बाध्य होंगे। इसके कारण भारतीय समाज में जातिगत बन्धन और अधिक ढीले पड़ने लगेंगे।
अर्न्तजातीय विवाहों की दर में वृद्धि होगी। अर्न्तराज्यीय विवाहों का प्रचलन अभी भी बढ़ता दिखायी देने लगा । इससे जातीय संरचना में तीन वृहद श्रेणियाँ ध्रुवीकृत (polarized) होंगी।

(1) उच्च जातियों का एक वर्ग – जिसकी सम्बद्धता भूमंण्डलीकृत व्यवस्था में सर्वाधिक होगी।

(2) मध्य क्रम की वे जातियाँ – जिन्हें आज अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के नाम से जाना है, ये जातियां भी भूमंडलीकृत व्यवस्था में सम्बद्ध (Connect) होने का प्रयास करेंगी परन्तु अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण प्रारम्भिक दौर में अपेक्षाकूल कम सफलता प्राप्त करेंगी।

(3) "दलित" जातियों का वर्ग – यद्यपि यह वर्ग राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय है, परन्तु भूंमण्डलीकरण की प्रक्रिया में यह पिछड़ सकता है। इसका प्रमुख कारण इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति व सामाजिक – सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व साधनों का अभाव है।

शिक्षा तथा व्यवसाय में आरक्षण की नीति पर भी भविष्य में प्रश्न खड़े होंगे। सार्वजतिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने के समर्थन तथा विरोध में तीव्र आन्दोलनों का जन्म हो सकता है। जिससे तनाव व संघर्ष का माहौल बनेगा तथा जातियों का ध्रुवीकरण और बढ़ेगा। इलाहाबाद में आरक्षण विरोध/समर्थक आन्दोलन इसी प्रकार की प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं।

सामाजिक संस्तरण की दूसरी प्रमुख श्रेणी – वर्ग संरचना है। भूमण्डलीकरण से वर्ग संरचना का रूपान्तरण भी निश्चित है। आर्थिक एवं शैक्षणिक असमानता में वृद्धि के कारण व्यवसायिक संरचना भी तेजी से बदल रही है साथ ही कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना तकनीकी का भारी मात्रा में उपयोग भी इसे प्रभावित कर रहा है। जिसके कारण निचले वर्ग के व्यवसायों में काफी कमी आ रही है। इस वर्ग के लोगो के लिए रोजगार के नये अवसरों की कमी होने से इसनें असंतोश, आक्रोश तनाव, संघर्ष उत्पन्न होगा। इस वर्ग में विशेष रूप से लोग सम्मिलित होंगे जो भूमडलीकरण के दौर में स्थानीय उद्योग धन्धों के बन्द हो जाने के कारण मूल्यविहीन (Devalued) होकर बेरोजगार तथा गरीब हो जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि मजदूर, सीमान्त किसान, व लघु किसान भी भूमण्डलीकरण के पहले शिकार होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप इनका पलायन शहर की और होने की आशंका है। जिससे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में भारी वृद्धि होगी। साथ ही छोटे कस्बों तथा नगरों में आवश्यक, मूलभूत अभिसंरचनाओं का अभाव वहाँ पूंजी निवेश करने में बाधक होगा। अतः बड़े नगर ही विकास के केन्द्र बने रहेंगे। जिसके कारण भारी असमान विकास दृष्टिगोचर होगा, वहीं दूसरी ओर नवीन भूमंडली कृत 'बाजार व्यवस्था' विशेषतः इन समाजों की व्यवसायिक संरचना के उच्च एवं मध्य स्तर पर नवीन वर्गों (classes) को जन्म दे रही है जैसे कारपोरेट सेक्टर में सूचनाकर्मियों (information workers) का एक नया वर्ग (class) जो मार्क्स के श्रमिक की तुलना में काफी पढ़ी लिखा है तथा उच्च जीवन शैली (high style of life) में विश्वास रखता है।

सामाजिक स्तरीकरण का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष शक्ति संरचना (power structure) है। इस पर भी भूमंडलीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। राजनेताओं का अर्थव्यवस्था में नियन्त्रण कम हुआ है। वे इसे समझ पाने में असमर्थ है। मंहगाई पर नियन्त्रण इनके बस से बाहर है। आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) पर भी इनका नियन्त्रण नहीं है। जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न होगा तथा राजनेताओं की साख में गिरावट आयेगी। राजनीतिक

शक्ति का केन्द्र समाज की दूसरी संस्थाओं जैसेः– मानव अधिकार संगठन (Human Right organization), गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), नागरिक समाज (civil Society) के हाथों में हस्तांतरित होगा तथा वैश्विक (Global) तथा स्थानीय (local) दोनों स्तरों पर तथा इनके द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अन्ना हजारे का आन्दोलन तथा आम आदमी पार्टी का उदय इसी प्रकार की घटनाओं में आती है। इस प्रकार की संरचनाएं पुरानी राजनीतिक संरचनाओ के ढांचे में फिट नहीं हो पायेंगी तथा नवीन प्रकार की राजनीकि संरचनाओं का कालान्तर में उदय होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखायी दें रहे है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा (Higher Education) का भूमंडलीकरण (Globalization) बड़ी तेजी से हो रहा है। जिससे वर्तमान विश्वविद्यालयों को भी स्वयं को नयी अर्थ–व्यवस्था के साथ सामंजस्य विठाना होगा। नये–नये कोर्सों का आरम्भ, विदेशों में शिक्षा के लिए अधिक लोगों का जाना इसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। परन्तु साथ ही वे लोग जिनकी शिक्षा आज की वैश्विक व्यवस्था में अनुरूप नहीं है उनका पृथक्कीकरण (Exclusion) भी कालान्तर में निश्चित है।

इसी प्रकार विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार– बड़े सुविधायुक्त अस्पतालों का उदय स्वास्थ्य पर्यटन (health tourism) को बढावा दे रहा है। जिससे सरकारी व निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिस्पर्धा होगी तथा अन्ततः इनका निजीकरण होने की सम्भावना अधिक दिखायी देती है।

सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में भूमंडलीकरण प्रतिमान संरक्षण (Pattern maintenance) के लिए उत्तरदायी संगठनों को प्रभावित करता है। इसमें जनमत (Public Opinion) का निर्माण करने में जन संचार माध्यमों (Mass media Communication) तथा नयी संचार तकनीकियों, जिनमें चौबीसों घंटे प्रसारित होने वाले टी.वी. चैनलों के कार्यक्रम, इन्टरनेट का बढ़ता प्रभाव तथा मोबाइल फोन द्वारा लयी जा रही संचार क्रान्ति सांस्कृतिक क्षेत्र में नये–नये परिवर्तनों को जन्म देगी तथा नये सूचना तन्त्र के माध्यम से समाज में एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगी। जिससे पृथक्कीकरण (Exclusion) को कम करने में सहायता मिलेगी।

धार्मिक क्षेत्र में नये–नये किस्म के संगठनों का उदय हो रहा है जो लोगों को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रभावित करेंगे तथा धर्म के सार्वभौमिक अपील (universal Appeal) करने वाले तत्वों को प्रचारित करने हेतु इनका भी भूमण्डलीकरण भी स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है। इनके द्वारा जन संचार माध्यमों तथा नयी संचार तकनीकी का भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। जिससे विभिन्न स्तरों पर नये धार्मिक आन्दोलनों का उदय होगा।

इस प्रकार से हम देखते है कि भूमण्डलीकरण भारतीय समाज व संस्कृति के प्रत्येक्ष क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि भूमण्डलीकरण मात्र आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं है अपितु एक बहुआयामी (Multidimensional) तथा जटिल प्रकियाओं को स्वयं में समाहित किये हुए है तथा इसके फलस्वरुप विभिन्न समाजों में संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक स्तर पर रूपान्तरण देखे जा सकते है। यह संस्कृति के (homogenization) की प्रक्रिया नही अपितु इसके द्वारा बहुसांस्कृतिकवाद (Multi-culturalism) को बढावा मिलेगा परन्तु अभी यह प्रक्रिया अपने प्रारम्भिक दौर में ही है। इसके आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अपेक्षाकृत रूप से अधिक स्पष्ट है। अन्य पक्षों को पूर्ण रूप से उद्घाटित होना अभी शेष हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अटल, योगेश 1968ः चेंजिंग फ्रंअियर्स आफ कास्ट, दिल्लीः नेशनल पब्लिशिंग हाउस।

गिडिन्स, एन्थोनी 1999ः गलोबलाइजेशन, डायरेक्टर्स लेक्चरः *10 November, 1999, http://www.lse.ac.uk/Giddens/reith_99/default.html.*

सिंह, वी. पी. 2004 : ग्लोबेलाइजेशन, न्यू मीडिया टेक्नॉलोजीस़ एण्ड सोशियो–कल्चरल चेंज इन इन्डिया, इर्मिजिंग ट्रेंडस् इन डवलेपमेंट रिसर्च,, वाल्यूम 11, नं. 1–2, पेज 3–9.

सिंह, वी. पी. एण्ड रुपा रानी टी. एस. 2005 : ग्लोबेलाइजेशन, न्यू मीडिया टेक्नॉलोजीस़ एण्ड एजुकेशनउ अमॉग दी मुस्लिम माइनोरिटिस इन इन्डिया, इर्मिजिंग ट्रेंडस् इन डवलेपमेंट रिसर्च, वाल्यूम 12, नं. 1–2, पेज 3–16.

सिंह, वी. पी. 2007 : ग्लोबेलाइजेशन एण्ड सोशल स्ट्रेटीफिकेशन इन इन्डिया, *इर्मिजिंग ट्रेंडस् इन डवलेपमेंट रिसर्च,* वाल्यूम 14, नं. 1–2, पेज 1–8.

सिंघल, अरविन्द एण्ड ई. एम. रोजर्स 2001ः इन्डियाज कम्यूनिकेशन रिवोल्यूशन, न्यु देहलीः सेज पब्लिकेशन

हेल्ड, डेविड, मैकग्रयु, ए., गोल्ड ब्लेट., डेविड तथा पेरेटन जे. 1999ः *ग्लोबल ट्रांसफॉरमेशंस– पालिटिक्स, इकोनोमिक्स एण्ड कल्चर,* केम्ब्रिजः पालिटी प्रेस।